



अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग

■ सड़कों पर उतरे कई संगठनों के लोगों ने किया प्रदर्शन



एजेंसी कोटद्वार। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले काग्रिस कार्यकताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकताओं ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार साक्षी उपाध्याय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। सोमवार को विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी देवी मंदिर चौराहे में एकत्र हुए। यहां से उन्होंने नगर में रैली निकाल प्रदर्शन किया। रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील पहुंचकर सभा में तब्दील हुई। इस मौके पर वकाओं ने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्याकांड के बाद से ही उत्तराखंड की जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है। कहा कि शुरुआत से ही प्रदेश की जनता वीआईपी के नाम का खुलासे की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

दिल्ली: लक्ष्मी नगर इलाके में दबंगों की गुंडागर्दी

■ बाप-बेटे के कपड़े उतारकर बेरहमी से पीटा



एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में 2 जनवरी को हुई एक खौफनाक घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां दबंगों के एक गिरोह ने एक बाप-बेटे को न केवल बेरहमी से पीटा, बल्कि युवक को नंगा कर सड़क पर घसीटते हुए भी पीटा। हैरत की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में भी दबंग युवक को घसीटते रहे, लेकिन वे मुकदर्शक बने रहें। इस बर्बरता का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों की हैवानियत साफ दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार, पीड़ित के घर में ज़िम खोला हुआ है, जिसे लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव और पिंदू यादव ने पीड़ित के बेटे को पीटा, फिर उसे घसीटकर सड़क पर ले आए और नंगा कर जूतों से मारा। इस दौरान उसके दांत भी तोड़ दिए गए और सिर पर भी गंभीर चोटें आईं। उसके पिता को भी ज़िम में नंगा कर पीटा गया। बदमाशों ने पीड़ित को पत्नी के साथ भी मारपीट की। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे भीड़ तमाशगिन बनी खड़ी रही और किसी ने भी पीड़ित बाप-बेटे को बचाने की जहमत नहीं उठाई।

भाजपा नेता संगीत सोम को बांग्लादेश से धमकी, सरधना थाने में एफआई दर्ज

मेरठ। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता ठाकुर संगीत सोम को बांग्लादेश से धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। धमकी भरे फोन कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल मिलने के बाद उन्होंने सरधना थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। भाजपा नेता संगीत सोम ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे उन्हें धमकी भरे मैसेज और वीडियो कॉल प्राप्त हुए। इन कॉलस और मैसेज में उन्हें जान से मारने के साथ-साथ कुछ प्रमुख न्यूज चैनलों को उड़ाने की धमकी दी गई। उन्होंने सभी संदिग्ध



नंबर पुलिस को जांच के लिए सौंप दिए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धमकी देने वाले नंबर बांग्लादेश के हैं। साइबर सेल और अन्य तकनीकी एजेंसियों की मदद से पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि धमकी देने वालों की पहचान की जा सके। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को संगीत सोम ने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल में शाहरुख

खान की टीम द्वारा खरीदे जाने को लेकर बयान दिया था। इस बयान के बाद देशभर में चर्चा शुरू हुई और बाद में बीसीसीआई ने उस खिलाड़ी को टीम से रिलीज करने का फैसला लिया। इसी घटनाक्रम के बाद धमकी मिलने की आशंका जताई जा रही है। धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए संगीत सोम ने साफ कहा कि वह सनातन धर्म और सनातनियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियों से वह डरने वाले नहीं हैं और देश व समाज के हित में अपनी बात मजबूती से रखते रहेंगे। सरधना थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

डेरा मुखी राम रहीम सिरसा डेरा पहुंचा:15वीं बार जेल से बाहर आया

एजेंसी रोहतक। सुनारिया जेल में साध्वियों के यौन उत्पीड़न और पत्रकार की हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। उसे 40 दिन की पैरोल मिली है। सोमवार को राम रहीम को लेने के लिए सिरसा डेरे से लाजपरी गाड़ियों का काफिला पहुंचा, जिसमें दो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, दो फॉल्कस्वर और दो अन्य गाड़ियां शामिल थीं। सुबह करीब साढ़े 11 बजे वह सुनारिया जेल से सिरसा डेरे के लिए निकला। दोपहर 2:45 बजे वह सिरसा पहुंचा। इस बार



डेरा मुखी 15वीं बार पैरोल या फरलो लेकर जेल से बाहर आया है। इससे पहले डेरा मुखी राम रहीम 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने के लिए जेल से बाहर आया था। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने कहा, "हर कैदी का पैरोल और फरलो का अधिकार होता है। इसके तहत कैदी को एक साल में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो मिलती है। ऐसा नहीं है कि इस पैरोल और फरलो का लाभ सिर्फ गुरुजी को मिलता है।

सही समय पर सटीक जानकारी कितनी जरूरी है। एआई और ऑटोमेशन का भरपूर इस्तेमाल होगा। यह तीन स्तंभों डेटा, नेटवर्क और फौजी आंकड़ों पर खड़ा होगा। साइबर तंत्र के माध्यम से तय होगा कि कौन-सी जानकारी कहाँ से आएगी और उसे कैसे सुरक्षित रखा जाएगा।

सेना देशभर में फैले अपने डिजिटल नेटवर्क, डेटा सेंटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम सेंटरों का साझा प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। इससे जंग के मैदान में तैनात सैनिक से लेकर कमांडर तक सबको अपडेट जानकारी मिलेगी।

योगी सरकार का बड़ा फैसला,

पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर दी बड़ी राहत



एजेंसी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी

कर दिया गया है। सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों को भरे जाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह आयु शिथिलीकरण एक बार के लिए प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा यह



निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के आलोक में लिया गया है। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी

शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। योगी सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं

की वास्तविक समस्याओं को समझती है और समाधान के लिए ठोस फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना योगी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया बल देना, बल्कि यह भी दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है।

रेलवे ब्रिज के शिलान्यास पर छिड़ सियासी संग्राम

■ मंत्री के सामने भिड़े कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ता



एजेंसी बेंगलूरु। रेलवे ओवरब्रिज के शिलान्यास कार्यक्रम में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यह पूरा घटनाक्रम केंद्रीय मंत्री वी. सोमना की मौजूदगी में हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि कार्यक्रम स्थल पर कुर्सियां उछलने लगीं और पुलिस को हालात संभालने के लिए बीच में आना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक, कार्यक्रम स्थल पर लगे बैनरों में जिला प्रभारी मंत्री शिवराज तंगड़गी और कोपल के सांसद राजशेखर हितनाल के नाम नहीं थे। इसी बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री के पहुंचते ही इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का

आरोप था कि जानबूझकर राज्य सरकार के मंत्री और स्थानीय सांसद के नाम हटाए गए। इसे अपमान बताते हुए उन्होंने विरोध शुरू किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका जवाब दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि मामला हाथपाई तक पहुंच गया। हालात तब आगे बिगड़े, जब मंच के पास कुर्सियां फेंकी जाने लगीं। पुलिसकर्मियों को आगे बढ़कर भीड़ को काबू में करना पड़ा। कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पूरी तरह अव्यवस्थित हो गया। पुलिस के सांसद राजशेखर हितनाल के अलग-अलग कर हालात शांत कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार, हंगामे के दौरान केंद्रीय मंत्री सोमना ने कथित तौर पर कांग्रेस समर्थकों के लिए पतालम शब्द का इस्तेमाल किया।

ट्रम्प ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को धमकी दी

कहा : हमारी बात नहीं मानी तो और बुरा हाल करेंगे, यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग

एजेंसी नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगज को बुरा हाल करने की धमकी दी है। ट्रम्प ने कहा, 'अगर डेल्सी वह नहीं करती तो वेनेजुएला के लिए एमेरिका सही मानता है, तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है।' ट्रम्प ने यह बात द अटलांटिक मैगजिन को दिए इंटरव्यू में कही है। इससे पहले ट्रम्प ने कहा था- अगर रोड्रिगज अमेरिका की बात मान लेती हैं तो वेनेजुएला में अमेरिकी सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, रोड्रिगज ने मादुरो को सत्ता से हटाने की आलोचना की है। साथ ही अमेरिका से मादुरो को वापस भेजने की मांग की है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद आज वरुडर की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की हिरासत में लेने की वधेघात पर चर्चा होगी। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगज ने अमेरिका से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला अमेरिका के साथ विकास और शांति के लिए सहयोग का एजेंडा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा, शुरू होने में अभी कई महीने लग सकते हैं। अमेरिकी सैनिकों ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला पर



मादुरो का हमेशा रहा है और आज पूरे वेनेजुएला का भी यही संदेश है। रविवार देर रात जारी किए बयान में रोड्रिगज ने कहा कि अमेरिकी सेना को कार्यवाई में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद भी वेनेजुएला टकराव नहीं, बल्कि संवाद और सहयोग चाहता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आज मैनहटन की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मादुरो ने अमेरिका में हथियार और ड्रग तस्करी के आरोप हैं। शनिवार को मादुरो की पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को भी केस में शामिल किया गया है। उन पर अपहरण और हत्याओं के आदेश देने का आरोप लगाया गया है। मादुरो ने इस तस्करी से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। उनके मुकदमे की सुनवाई बनाया जाएगा है। उन्होंने कहा, शुरू होने में अभी कई महीने लग सकते हैं। अमेरिकी सैनिकों ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला पर

हमला कर मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को अगवा कर लिया था। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है। जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उन पर हथियार-ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। चीन ने मादुरो को गिरफ्तार करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि कोई भी देश खुद को 'डुनिया का जज' या 'डुनिया की पुलिस' नहीं मान सकता। बीजिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात के दौरान वांग यी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हर देश की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने वेनेजुएला की स्थिति का जिक्र किया, लेकिन सीधे तौर पर अमेरिका का नाम नहीं लिया। उन्होंने भी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही उनकी चीन के विशेष प्रतिनिधि से मुलाकात हुई थी। चीन 2017 से अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद वेनेजुएला को आर्थिक सहयोग देता रहा है। 2024 में चीन ने वेनेजुएला से करीब 1.6 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जिसमें लगभग आधा कच्चा तेल था।

2026 के लिए भारतीय सेना का रोडमैप तैयार

शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में प्लानिंग, एआई, डेटा और डिजिटल नेटवर्क से होगी अगली जंग

एजेंसी नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ 88 घंटे की जंग के विश्लेषण के बाद सेना ने अहम बदलावों की रूपरेखा तैयार की है। सेना ने इसे तीन हिस्सों अल्पकालिक (शॉर्ट टर्म), मध्यकालिक (मीडियम टर्म) और दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) रणनीति में बांटा है। अल्पकालिक रणनीति के तहत 2026 का स्पष्ट रोडमैप बनाया गया है। सेना के सूत्रों ने बताया कि इस साल पूरा जोर हथियार हासिल करने की बजाए युद्ध के पूरे वातावरण की त्वरित जानकारी, नेटवर्क और तेज



फैसलों पर केंद्रित रहेगा जो ऑपरेशन सिंदूर का अहम सबक है। सेना ने साल 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिफिटी और 2027 में ऑपरेशंस के एआई से पूर्ण इंटीग्रेशन के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस प्रक्रिया से

जुड़े शीर्ष अधिकारी ने बताया कि यह फैसला सेना की लंबे समय से चल रही परिवर्तन योजना का अमला कदम है। सेना ने साल 2023 से 2032 को परिवर्तन का दशक घोषित किया है। इसके तहत 2023 में संगठन, सोच और काम

करने के तरीकों में सुधार 2024 को तकनीकी आत्मसात और 2025 में जमीनी स्तर पर बदलाव का रोडमैप अपनाया गया है। स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन में भी बदलाव किए जा रहे हैं। योजना यह है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों, दुश्मन और घरेलू कम्युनिकेशन के लिए अलग-अलग कंटेंट और माध्यम तय हों। नैरेटिव वॉर में दुश्मन के झूठ तंत्र को फेल किया जाए। राजनीतिक नेतृत्व, तीनों सेनाओं के बीच संवाद और मीडिया के साथ तालमेल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सेना की स्टडी में सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान

सही समय पर सटीक जानकारी कितनी जरूरी है। एआई और ऑटोमेशन का भरपूर इस्तेमाल होगा। यह तीन स्तंभों डेटा, नेटवर्क और फौजी आंकड़ों पर खड़ा होगा। साइबर तंत्र के माध्यम से तय होगा कि कौन-सी जानकारी कहाँ से आएगी और उसे कैसे सुरक्षित रखा जाएगा।



अपने हित हेतु वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला

(लेखक-संजय गोस्वामी)

अमेरिकी आर्मी ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है. उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूएस वेनेजुएला का शासन संभालेगा. इससे पहले ट्रंप ने हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे मादुरो की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह एक अमेरिकी युद्धपोत पर सवार थे. उधर, लैटिन अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन समेत कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की निंदा की और तनाव कम करने की अपील की. वहीं, कराकस में अमेरिकी हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं. यह खेल दरअसल इस का नहीं कच्चे तेल के व्यापार का है जहाँ उसे फायदा दिख रहा है कोई देश क्या कर रहा है इसपर अमेरिका क्यों दखल देता है ऐ उसके सम्प्रभुता पर गहरा चोट है आप अपने पास क्या रखते क्या खाते है क्या पहनते हैं क्या कारोबार करते हैं यह आंतरिक मामला है इसलिए अमेरिका को इसमें दखल नहीं देना चाहिए लेकिन बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है इसलिए वहाँ तेल का सबसे बड़ा निर्यात है अरबों डालर का व्यवसाय है जिसने रूस और चीन के साथ करार किया और अमेरिका को नहीं शामिल किया इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ तेल के व्यापार पर अपने नियंत्रण की बात भी कह दि और शासन भी चलाएगा दरअसल अब सभी देशों को इससे सिख लेनी चाहिए यदि आपके पास ताकत है रक्षा का बजट जितना ज्यादा है रक्षा पर जितना हथियार है सब ले लो और परमाणु हथियार जरूर रखो ना कि निर्दोष लोगों को जैसे 1945 में अमेरिका ने हीरोशिमा और नागासाकी पर गिरा कर लाखों लोग को मौत के घाट उतार दिए बल्कि अपने देश के आत्मरक्षा हेतु जरुरी है क्योंकि एटम बम का अब खेल हो रहा है जहाँ नहीं है वहीं अमेरिका अटंक करेगा और अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने के बाद ही अपने को सुपर पावर समझता है अतः देश पहले है आत्मरक्षा हेतु यह जरुरी है कि ऐसा हथियार मेरे पास है जो आग बनकर बरसेगा, और देश के ऊपर यदि गलती से

ऑख उठा कर देखा तो विनाश भी देख लेना भगवान शंकर हमेशा शांत ही रहते हैं ध्यान में लेकिन यदि उनकी शांति भंग हुई तो तांडव भी कर सब बर्बाद करने की ताकत है यही कारण है कि जब भारत ने अमेरिका के दबाव के बाद भी 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण किये तो दूसरा देश डरा था ऐ हमारे वैज्ञानिकों और अटलजी का देश के प्रति निष्ठा थी जिसमें सफलता मिली और भारत को अमेरिका से सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि आए दिनों जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिका का सपोर्ट आतंकवादी को सजाने के लिए किया वो भारत के ऊपर एक घेरने की रणनीति बना रहा है अमेरिका में खुद 6000 के करीब परमाणु अस्त्र हैं फिर भी परीक्षण करता रहता है केवल डराने के लिए और भारत के आंतरिक मामलों और व्यापार पर निगाहें गड़ा रहा है नहीं चाहिए ऐ व्यापार और उसके साथ कोई भी परमाणु सयन्त्र लगाने की जरूरत क्योंकि बाद में अमेरिका के सीआईए के एजेंट भी कई देशों में है और जब वो रातोंरात वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति को बंधक बनाया उससे ऐ साबित होता है कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं जो अपराध की श्रेणी में है ईरान में भी सीआईए के एजेंट थे और उसके घर में घुसकर बंकर ब्लस्टर बम से उसके परमाणु सयन्त्र को नष्ट कर बजापते ऐ कहना कि अमेरिका जो कर सकता है वो कोई नहीं ऐ एक पहले ही धमकी को हकीकत में बदलने की शुरुआत हो गई थी और सीरिया में सत्ता परिवर्तन में भी अमेरिका का हाथ था आखिर इतना हथियार कौन देगा और अचानक कुछ ही हफ्तों में रिजिम चेंज कारना इसलिए भारत में तमाम टीवी चैनल को अब भारत की किसी भी सत्ता या देश की समस्या को दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे विदेशी ताकत हावी होते हैं और इसका लाभ परोसी दुश्मन देश को मिलता है और यदि सत्ता परिवर्तन चाहिए तो भारत में लोकतान्त्रिक व्यवस्था है उससे आप कर सकते हैं लेकिन जिसका ना कोई सर है ना पैर कि 19 नवंबर 25 को नया प्रधानमंत्री मिलेगा वोट चोरी और अड़ानी अम्बानी पर ध्यान देना ठीक नहीं है ना ही ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करना अब हमें शांति से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जमीनी धरातल पर खासकर रक्षा के क्षेत्र में कार्य करने

की आवश्यकता है क्योंकि युद्ध करना आज आसान नहीं है इसमें दूसरे देश भी शामिल हो जाते हैं और हमारे सेना को हमेशा तारीफ करना चाहिए जो देश की रक्षा करते हैं जैसा की मालूम है की वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर से पहुंचे गए. इसके बाद उन्हें भारी सुरक्षा वाले बख्तरबंद मोटरकेड में ड्रग एनकोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ष्ठ) के दफ्तर ले जाया गया, क्योंकि मादुरो पर ड्रग तस्करी और नार्को-टैररिज्म के गंभीर आरोप हैं .वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर किए गए अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है. अमेरिका ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एक्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि फिलहाल वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा.वेनेजुएला के पास सेना बहुत है लेकिन न्यूविलयर हथियार नहीं है इसलिए अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है इसमें चीन और रूस अमेरिका से नहीं लड़ेगा क्योंकि उसे मालूम है इससे उसका भी काफी नुकसान होगा और दूसरी तरफ रूस खुद ही यूक्रेन के युद्ध में फंसा है इसलिए वो भी इसमें उलझना नहीं चाहेगा क्योंकि यदि उलझना होता तो ईरान के युद्ध में या सीरीया के तख्तापलट पर ही उलझ जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं वेनेजुएला ने एटम बम क्यों नहीं बनाये क्योंकि उसने डर से सीटीवीटी पर हस्ताक्षर कर दिए थे

वेनेजुएला के न्यूविलयर एनर्जी प्रोग्राम 1950 के दशक में शुरू हुए थे, लेकिन अभी कोई एक्टिव न्यूविलयर पावर फैसिलिटी नहीं है। वेनेजुएला की ज्यादातर न्यूविलयर साइंस एक्टिविटीज वेनेजुएला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च (IVIC) में होती हैं। वेनेजुएला ने 2017 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में **TPNW** की बातचीत में हिस्सा लिया था और उन 122 देशों में से एक था जिन्होंने इसे अपना



के पक्ष में वोट दिया था।

बातचीत कॉन्फ्रेंस में अपने शुरुआती बयान में, वेनेजुएला ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मिलकर एक मजबूत और ठोस फाइनल डेव्यूमेंट हासिल करेंगे जो न्यूविलयर हथियारों पर रोक लगाएगा, जो उनके पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में एक शुरुआती कदम होगा।

अपने आखिरी बयान में, उसने कहा कि न्यूविलयर हथियारों का कोई भी इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ अपराध है, और जोड़ा- कोई भी सुरक्षा सिद्धांत, किसी भी देश का कोई भी राष्ट्रीय हित, कोई भी मिलिट्री ब्लॉक इंसानों की बड़े पैमाने पर हत्या या ग्रह के विनाश को सही नहीं ठहरा सकता। जीवन और शांति का तर्क जीतना चाहिए।

2016 में, वेनेजुएला ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के उस प्रस्ताव को को-स्पॉन्सर किया था जिसने देशों के लिए न्यूविलयर हथियारों पर रोक लगाने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज पर बातचीत शुरू करने का औपचारिक आदेश स्थापित किया, जो उनके पूरी तरह से खत्म करने की ओर ले जाएंगा लेकिन यदि हिम्मत बांध कर कर लिया होता तो अमेरिका का हमला नहीं होता क्योंकि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है और आत्मरक्षा हेतु परमाणु हथियार जरुरी है जिससे डर हो।

संपादकीय

वेनेजुएला पर हमला

पिछले लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी हमले के बाद गिरफ्तार करना निस्संदेह, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाना अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी का दुर्लभ उदाहरण है। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता परिवर्तन होने तक वाशिंगटन इस लैटिन अमेरिकी देश का संचालन करेगा। यह एक खतरनाक परंपरा है, जिसकी पुनरावृत्ति अमेरिकी महाद्वीप से बाहर होने की आशांका भी बलवती हो सकती है। इसमें दो राय नहीं कि निकोलस मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला में मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से मादुरो को लगातार खलनायक बनाने की कोशिशों में एक वैश्विक तंत्र लगा हुआ था। वैसे आरोप मादुरो पर लगे कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया, असहमतियों को कुचला और लाखों लोगों को निर्वासन के लिये मजबूर किया। उन पर चुनाव में धांधली और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन वैश्विक कूटनीति के जानकार मानते हैं कि ट्रंप के इस दांव का लक्ष्य तानाशाही के पीड़ितों को न्याय दिलाने या इस देश की संप्रभुता की रक्षा के बजाय वेनेजुएला के समृद्ध तेल भंडारों पर नियंत्रण हासिल करना ज्यादा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा सैन्य अभियान चलाकर देश से बाहर किसी शासनाध्यक्ष को गिरफ्तार करना तथा वहां की सत्ता को वाशिंगटन से संचालित करना निश्चय ही साम्राज्यवादी सोच का ही पर्याय है। निस्संदेह, इस अमेरिकी निरंकुशता के गहरे भू-राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे। यहां तक कि मादुरो का विरोध करने वाले अमेरिका के सहयोगी देश भी, अब मुखर होकर चेतावनी देने लगे हैं। रूस और चीन इस अमेरिकी कार्रवाई को नियम-कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिये खतरा बता रहे हैं। वहीं वेनेजुएला के इस घटनाक्रम ने चीन को अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर अमेरिकी आलोचना को बेअसर करने का भरपूर मौका दे दिया है। जिससे ताइवान की चिंताएं बढ़ सकती हैं। अमेरिका के इस कृत्य ने इराक और अफगानिस्तान में हमले व सेना की तैनाती की यादें ताजा कर दी हैं। ऐसे युद्ध जो अमेरिकी आत्ममुग्धता और अति-आत्मविश्वास से शुरू हुए, लेकिन उनका समापन अपमानजनक विदाई से हुआ। लेकिन इन हमलों के बाद वे देश कभी सामान्य नहीं रह पाए। वहीं ट्रंप की यह दलील कि मादुरो को पकड़ने के लिये चलाए अभियान का खर्च वेनेजुएला के तेल राजस्व से वसूला जाएगा, उसके प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिकी नियंत्रण की मंशा को ही दर्शाता है। वहीं अमेरिका ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सुशासन, सुरक्षा के लिये वेनेजुएला की जनता की आकांक्षाओं वाले किस नेता को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। भारत भी उन देशों में शामिल है, जिन्होंने घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। जो सही मायनों में भविष्य की वैश्विक चिंताओं के अनुरूप ही है। बहरहाल, देर-सवेर ट्रंप को अहसास होगा कि एक निरंकुश शासक को हटाना आसान है, लेकिन उस देश में दीर्घकालिक शांति-स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये गंभीर प्रयासों की जरूरत होती है।



वैश्विक कानून: जिसकी लाठी उसकी भैंस?

(लेखक-सनत जैन)

राष्ट्रपति बंधक, वेनेजुएला में तख्तापलट

अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है। वैश्विक व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय कानूनों में नैतिकता और न्याय का कोई स्थान नहीं है। हर देश की ताकत निर्णायक है। जिस तरह एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति पर हमला करके कथित तौर पर पति-पत्नी का अपहरण कर बंदी बनाया गया है। उसने सारी दुनिया को हतप्रभ कर दिया है। यह घटना किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं है। यह घटना अंतरराष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक संबंधों और राष्ट्रों की संप्रभुता पर सीधा हमला है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी यह घटना एक बड़ी चुनौती है।

अमेरिका स्वयं को मानवाधिकार एवं लोकतांत्रिक कानून का सबसे बड़ा संरक्षक बताता है। इस घटना ने उसके दोहरे मापदंडों को उजागर कर दिया है। अमेरिका के खाने वाले दांत अलग और दिखाने वाले दांत अलग हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है, किसी देश की राजनीतिक नेतृत्व संरचना में इस तरह का कृत्य पूर्ण रूप से अवैध है। इसके बावजूद अमेरिका ने ऋराष्ट्रीय सुरक्षाक्ष और ऋआतंकवाद के विरोधक्ष जैसे तर्कों की आड़ में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का ऐसे समय पर अपहरण किया है। जब 1 घंटे पहले ही चीन का एक प्रतिनिधि मंडल उनके साथ चर्चा कर रहा था। संदेश साफ है,शक्ति है, तो नियम अपने आप बन जाते हैं। रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश इस घटनाक्रम पर असहज हो गये हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका

और लैटिन अमेरिका के कई देशों में इस घटना के बाद यह आशंका पैदा हो गई है। इस तरह की घटना समर्थ देश किसी भी अन्य देश के साथ कर सकते हैं। वर्तमान में यह घटना वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ घटी है। भविष्य में किसी अन्य देश में ताकत के बल पर यह घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सबकी अपनी ढपल्टी और अपना राग होगा।

यह घटना वैश्विक राजनीति में भय एवं तोड़फोड़ का नया अध्याय है। छोटे और मध्यम देश अपने आप को अधिक असुरक्षित महसूस करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की खामोशी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में पहचाना जाता

है। पिछले कुछ वर्षों से इसे ऋविविध गुरुऋ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। भारत आर्थिक दृष्टि से सबसे तेजी के साथ बढ़ता हुआ देश है। इसकी ओर से इतनी बड़ी घटना पर कोई स्पष्ट और सशक्त प्रतिक्रिया नहीं आना भारत सहित वैश्विक मंच पर कई सवाल खड़े करता है। क्या भारत अमेरिका से इतना डरता है? रणनीतिक एवं व्यापारिक साझेदारी के नाम पर लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी पर भारत सरकार चुप रह सकती है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की आलोचना अब देश के अंदर बड़े पैमाने पर होने लगी है। मोदी सरकार कब तक चुपची साध कर इस तरह की घटनाओं से बच सकती है। दुनिया के देशों में जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। उसमें भारत सरकार

की चुप्पी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। वेनेजुएला की यह घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि किसी देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को इस तरह से अपहरण कर बंदी बनाया जा सकता है। भारत इतनी बड़ी घटना पर चुप रह जाता है। इस स्थिति पर दुनिया के देश भारत और भारत सरकार पर किस तरह से विश्वास करेंगे। इस तरह की घटना आम नागरिकों, पत्रकारों शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों की असहमति की आवाजों को क्या भारत में भी इसी तरह से दबाया जाएगा, तो आगे चलकर क्या होगा? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिस तरह से इस्तीफा कराया गया। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण और गिरफ्तारी पर अब लोग भारत में ही चर्चा एवं तुलना करने लगे हैं।

यह घटना केवल अमेरिका की दादागिरी और ताकत का प्रदर्शन मात्र नहीं है। बल्कि वैश्विक व्यवस्था को आपस में जोड़े रखने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए थे। जिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के ऊपर नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी थी। अंतरराष्ट्रीय जगत में उन संस्थाओं की कमजोरी और दयनीय स्थिति का यह एक आईना है। आज दुनिया को यह सोचने की जरूरत है, क्या अंतरराष्ट्रीय कानून सिर्फ कमजोर देशों पर लागू होंगे। शक्तिशाली देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून कागज की किताबों पर लिखे शब्द बनकर रह जायेंगे? अमेरिका द्वारा जिस तरीके से प्रतिबंधों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। विभिन्न देशों की पूंजी और संपत्ति को अमेरिका द्वारा मनमाने तरीके से जप्त किया जा रहा है।



माँ है तो सबकुछ है

माँ एक गुरु के रूप में अपनी संतान को संस्कार देती है। माता जीवन का निर्माण करती है, तो पिता उसे उन्नति के शिखर तक ले जाता है। माँ है तो सबकुछ है और यदि माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। जो अपनी माँ को प्रसन्न रखता है, वह उसके आशीर्वाद का वरदान भी पाता है। ऐसी परम उपकारी वात्सल्य मूर्ति माँ की आँखों में कभी आँसू नहीं आने देना। जो विनयपूर्वक परमात्मा और सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, वह सबकुछ पा जाता है। सद्गुरु हमें ज्ञान

देते हैं। सद्गुरुरूपी नाविक के साथ धर्मरूपी नौका में बैठकर इसान संसार सागर को पार कर लेता है। आज व्यक्ति धन-वैभव का अहंकार करता है, परंतु वह अंत में धराशायी हो जाता है। जिसके जीवन में विनय का गुण है, वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। माँ एक गुरु के रूप में अपनी संतान को संस्कार देती है। माता जीवन का निर्माण करती है, तो पिता उसे उन्नति के शिखर तक ले जाता है। माँ है तो सबकुछ है और यदि माँ नहीं तो कुछ भी नहीं।



उड़ाण के दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करना प्रतिबंधित- डीजीसीए

विमान में सीट में लगे पावर सॉकेट से भी पावर बैंक चार्ज करने की अनुमति नहीं

नई दिल्ली । विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए ने पावर बैंक और लिथियम बैटरी वाले उपकरणों से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत उड़ाण के दौरान पावर बैंक से मोबाइल, लैपटॉप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। अब विमान में सीट में लगे पावर सॉकेट से पावर बैंक चार्ज करना की भी अनुमति नहीं होगी। केवल हैंडबैग में पावर बैंक और अतिरिक्त बैटरियां ले जाने की अनुमति होगी। इन्हें चेक-इन बैगेज या ओवरहेड बिन में रखने की अनुमति नहीं है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों को नए नियमों के बारे में उड़ाण से पहले अवगत कराएं। यदि किसी डिवाइस में अत्यधिक गर्मी, धुआं, आग या अजीब गंध महसूस हो, तो यात्री को तुरंत केबिन क्रू को सूचित करना होगा। साथ ही, लिथियम बैटरी से जुड़ी किसी भी सुरक्षा घटना की रिपोर्ट डीजीसीए को तुरंत देना एयरलाइंस के लिए अनिवार्य होगी। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक यात्री, एक हैंडबैग नियम को सख्ती से लागू करना जरूरी है। ओवरहेड बिन में हैंडबैग भर जाने पर एयरलाइंस अक्सर उन्हें कार्गो होल्ड में रख देती हैं, जिससे लिथियम बैटरी के कारण जोखिम बढ़ सकता है। एमिरेट्स एयरलाइंस और सिंगापूर एयरलाइंस ने पहले ही उड़ाण के दौरान पावर बैंक के इस्तेमाल और चार्जिंग पर रोक लगा दी थी। नियम के अनुसार यात्रियों को केवल 100 वाट-घंटे से कम क्षमता वाले पावर बैंक ही ले जाने की अनुमति है।

कैथे कार्गो ने भारत को रणनीतिक बाजार बताया

कंपनी हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे प्रमुख केंद्रों पर सेवाएं बढ़ाएगी

हॉंगकांग । हॉंगकांग स्थित हवाई मालवाहक संचालक कैथे कार्गो ने भारत को अपने लिए रणनीतिक बाजार बताया है। कंपनी वर्तमान में प्रति सप्ताह 13 मालवाहक उड़ाणें संचालित कर रही है- दिल्ली और चेन्नई के लिए पांच-पांच तथा मुंबई के लिए तीन। कैथे कार्गो के दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका खंड के प्रमुख अे धिकारी ने कहा कि भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के साथ कंपनी भारत में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है। उन्होंने भारत में 1953 से अपनी सेवाएं शुरू करने और 2000 में मालवाहक संचालन बढ़ाने का जिक्र किया। उन्होंने मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसी पहलों को निवेशकों के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला बताया। लॉजिस्टिक क्षेत्र में विस्तार और लागत कम करने के अवसरों को भी उन्होंने रेखांकित किया। कैथे कार्गो के निर्देशक ने कहा कि को-टर्मिनलाइजेशन के माध्यम से कंपनी हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे प्रमुख केंद्रों तक सेवाएं बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में मांग बढ़ रही है और व्यवसाय के अवसर भी लगातार मजबूत हो रहे हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल ऋण 19.61 फीसदी बढ़ा

- कुल कारोबार 5.95 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

नई दिल्ली । बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही में कुल ऋण में 19.61 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की। इस दौरान बैंक का कुल बकाया ऋण बढ़कर 2.73 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 2.29 लाख करोड़ रुपये था। कुल ऋण में कॉर्पोरेट ऋण 1.02 लाख करोड़ और खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई (आरएमएम) ऋण 1.71 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। बीओएम का कुल कारोबार, यानी कुल ऋण और जमा, 17.24 प्रतिशत बढ़कर 5.95 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल दिसंबर के अंत में यह 5.08 लाख करोड़ रुपये था। चालू खाते और बचत खाते में भी मजबूत वृद्धि देखी गई। यह सालाना आधार पर 15.93 प्रतिशत बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 1.37 लाख करोड़ रुपये था।

बिना बिके घरों की संख्या में आया उछाल.....सबसे ज्यादा बुरी हालत बेंगलुरु के रियल एस्टेट बाजार की

मुंबई । भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए साल 2025 का अंत मिला-जुला रहा, एक ओर जहां नए प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आई, वहीं खरीदारों की मांग में आई नरमी ने बिना बिके घरों के आंकड़ों को ऊपर पहुंचा दिया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश के सात प्रमुख शहरों में बिना बिके घरों की संख्या में 4 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जिससे अब बाजार में करीब 5.77 लाख यूनिट्स खरीदारों का इंतजार कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु के रियल एस्टेट बाजार में सबसे

वेनेजुएला के तेल संकट पर अमेरिका की नजर, भारत के लिए अवसर भी

- देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, लगभग 303 अरब बैरल, लेकिन उत्पादन में गिरावट

नई दिल्ली । वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की 3 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद देश के तेल सेक्टर पर चर्चा तेज हो गई है। देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लगभग 303 अरब बैरल, लेकिन उत्पादन लगातार गिरता रहा है। 2010 में रोजाना लगभग 20 लाख बैरल तेल निकाला जाता था, जबकि नवंबर 2025 में यह घटकर केवल 9 लाख बैरल प्रति दिन रह गया। विशेषज्ञों के अनुसार वेनेजुएला में तेल उत्पादन तेजी से

बढ़ाना आसान नहीं है। सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए में लंबे समय से निवेश की कमी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण 2026 में केवल 1.5 लाख बैरल प्रति दिन की बढ़ोतरी संभव है। बंदरगाहों पर जहाजों को तेल भरने में पांच दिन लगते हैं, पाइपलाइन लीकेज हो रही हैं और कई रिफाइनरी बंद हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए अगले 10 साल में करीब 100 अरब डॉलर निवेश की जरूरत होगी। अमेरिका की तेल कंपनियां भारी कच्चा तेल निकालने में

दिलचस्पी दिखा सकती हैं। हालांकि, स्थिरता और सुरक्षा न होने के कारण बड़े निवेश में हिचकिचाहट है। भारत की कुछ सरकारी तेल कंपनियां पहले से पीडीवीएसए के साथ काम कर रही हैं। अगर निवेश और मशीनरी आसानी से मिलें, तो उत्पादन बढ़ सकता है। भारत पहले वेनेजुएला से रोजाना लगभग 4 लाख बैरल तेल मंगाता था, जो सस्ता और भारी कच्चा तेल होने के कारण रिफाइनरियों के लिए लाभकारी है।

अवांसे फाइनेंशियल ने 1200 करोड़ राइट्स इश्यू के जरिए जुटाए



नई दिल्ली । अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज, एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) ने मौजूदा शेयरधारकों वारंरग पिकंस, के दारा कैपिटल और अल्फा इन्वेस्टमेंट कंपनी एलएलसी से 1200 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह राइट्स इश्यू के माध्यम से हुआ। कंपनी का कहना है कि यह कदम शेयरधारकों के मजबूत विश्वास और विविध वित्तपोषण आधार को

मुम्बई । भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट एशियाई बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के बाद भी बिकवाली हावी रहने से आई है। आज कारोबार के दौरान गैस उर्जा और आईटी शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गयी जिससे भी बाजार टूटा। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 322.39 अंक नीचे आकर 85,439.62 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 78.25 अंक फिसलकर 26,250.30 पर बंद हुआ। आज निफ्टी रियल्टी,, निफ्टी इंडिया डिफेंस 2.04 , निफ्टी कंज्यूमर, निफ्टी एफएमसीजी में तेजी रही जबकि निफ्टी आईटी , निफ्टी ऑयल एंड गैस , निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी

वेनेजुएला में संकट के चलते शेयर बाजार में ऑयल कंपनियों के शेयरों में तेजी

मुकेश अंबानी को सबसे ज्यादा फायदा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर शिखर पर पहुंचे

नई दिल्ली । वेनेजुएला पर अमेरिका हमले के बाद सोमवार को शेयर बाजार में ऑयल कंपनियों के शेयरों में तेजी रही, खासतौर पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला संकट का सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर शिखर पर पहुंच गए हैं और नया रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर एक फीसदी से ज्यादा चढ़कर 1,611.8 रुपए प्रति शेयर के नए 52 हफ्ते के हई पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा ओपेनजीसी के शेयरों ने भी 2 फीसदी की तेजी दिखाई, लेकिन बाद में गिर गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज- आईओसी,

बीपीसीएल, और एचपीएसएल के शेयरों भी शुरुआती बढ़त के बाद गिरावट देखी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले के बाद सोमवार को कच्चे तेल की कीमतें थोड़ी बढ़ गईं, क्योंकि निवेशक यह सोच रहे थे कि ओपीसी सदस्य वेनेजुएला में राजनीतिक उथल-पुथल से सप्लाई वाले बाजार में शिपमेंट में कोई रुकावट आएगी। वहीं, कुछ एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि इस डेवलपमेंट से तेल की कीमतें कम होंगी। एक विश्लेषज्ञ ने कहा कि संभावित अमेरिकी अधिग्रहण से वेनेजुएला के कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज बेंट के मुकाबले डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद सकती है, जिससे कंपनी

एनएससी में 2,50,000 जमा करके पाएं 1,16,062 का फिक्स रिटर्न



- योजना पर मिलता है सालाना 7.7 प्रतिशत ब्याज

मुम्बई । नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) भारत सरकार द्वारा समर्थित एक ऐसा निवेश विकल्प है, जो जोखिम-मुक्त होने के साथ निवेशकों को निश्चित रिटर्न देता है। वर्तमान में इस योजना पर सालाना 7.7 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। ब्याज दर निवेश के समय तय होती है और पूरे निवेश अवधि के लिए स्थिर रहती है। ब्याज की गणना सालाना होती है, लेकिन भुगतान मैच्योरिटी पर एक साथ किया जाता है। एनएससी में निवेश करने का एक और प्रमुख फायदा यह है कि यह धारा 80सी के तहत टैक्स बचत का अवसर देता है। हर साल का ब्याज (अंतिम वर्ष को छोड़कर) भी टैक्स छूट के अंतर्गत आता है, जिससे निवेशक अपनी टैक्स प्लानिंग को बेहतर बना सकते हैं। इस योजना में हर साल मिलने वाला ब्याज फिर से निवेश माना जाता है, जिससे कंपाउंडिंग के आधार पर कुल रिटर्न बढ़ता है। एनएससी में सभी भारतीय नागरिक निवेश कर सकते हैं। हालांकि एनआरआई इसके अंत में निवेश नहीं कर सकते। यदि कोई निवेशक निवेश के बाद एनआरआई बन जाता है, तो वह मैच्योरिटी तक सर्टिफिकेट अपने पास रख सकता है। वयस्क अपने नाम पर, अभिभावक नाबालिग या मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति के नाम पर, और 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग स्वयं भी निवेश कर सकते हैं। यदि कोई निवेशक 2,50,000 एकमुश्त निवेश करता है, तो 5 साल में कुल रिटर्न लगभग 1,16,062 रुपए होगा। इस प्रकार मैच्योरिटी पर कुल राशि लगभग 3,66,062 रुपए हो जाती है।

रुपया गिरावट पर बंद मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ ही 90.30 पर बंद हुआ। आज सुबह शुरुआती कारोबार में रुपया चार पैसे टूटकर 90.24 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से रुपये में गिरावट आने के आसार हैं हालांकि कच्चे तेल की कम कीमतें कुछ हद तक राहत प्रदान कर सकती हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.21 पर खुला। शुरुआती कारोबार में और टूटकर 90.24 प्रति डॉलर पर आ गया। रुपया शुक्रवार को 22 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.20 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.50 पर रहा।



शेयर बाजार गिरावट पर बंद सेंसेक्स 322, निफ्टी 78 अंक गिरा



से अधिक अंकों की गिरावट के साथ 85,640 अंक पर खुला। शुरुआती कारोबार में बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। वहीं एनएसई का निफ्टी लगभग सपाट रुख के साथ 26,333 अंक पर खुला और 32.50 अंक की गिरावट के साथ 26,296 अंक पर ट्रेड करता दिखा। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली। जापान को छोड़कर एशिया-प्रशांत क्षेत्र का

भारत के आठ बड़े शहरों में ऑफिस स्पेस की मांग 25 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली । एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत के आठ प्रमुख शहरों में कार्यालय स्थान की मांग 25 फीसदी बढ़कर 6.14 करोड़ वर्गफुट हो गई। पिछले साल यह मांग 4.91 करोड़ वर्गफुट थी। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली-एनसीआर और चेन्नई में शुद्ध ऑफिस प्लेटे की मांग बढ़ी, जबकि मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद में गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि घरेलू और विदेशी कंपनियों की बढ़ती गतिविधियाँ, वैश्विक क्षमता केंद्रों का विस्तार और तकनीकी अपनाने में वृद्धि प्रमुख कारण हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़े केवल संख्याएं नहीं बल्कि दीर्घकालिक मजबूती और स्थायी वृद्धि का संकेत हैं। 2026 में भी ऑफिस स्पेस की मांग मजबूत रहने की संभावना है।



आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने रेपो रेट में कटौती का निर्णय लिया

महंगाई दर नियंत्रित, आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने की संभावना



नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने हाल ही में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में कटौती का निर्णय लिया है। समिति के एक सदस्य ने कहा कि महंगाई दर उम्मीद के अनुसार बनी हुई है और वर्तमान में कम स्तर पर है। अक्टूबर 2025 में समग्र महंगाई दर केवल 0.3 प्रतिशत थी, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित महंगाई दर 2 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि पिछले चरणबद्ध कटौती के असर से ऋण और जमा दरों में बदलाव महसूस किया गया है, और मौजूदा आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए 25 आधार अंक और कटौती की संभावना दिखाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च ट्रंप शुल्क के कारण कारोबार पर असर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में नीतिगत कदम लेने से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। समिति का यह निर्णय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और निवेश एवं व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है, जबकि महंगाई दर नियंत्रण में बनी हुई है।

संक्षिप्त समाचार

उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बारिश और ऊंची ज्वार से बाढ़, सड़कें बंद

कैलिफोर्निया, एजेंसी। उत्तरी कैलिफोर्निया में शनिवार को भारी बारिश और बेहद ऊंची ज्वार (किंग टाइड्स) के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई। अधिकारियों के मुताबिक, यह स्थिति पिछले करीब 20 वर्षों में सबसे गंभीर मानी जा रही है। बाढ़ की वजह से कई सड़कें बंद करनी पड़ीं और पानी में फंसी गाड़ियों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मैरिन काउंटी के शेरफ कार्यालय के अनुसार, सॉसालिटो से सैन राफेल तक करीब 24 किलोमीटर लंबे इलाके में सड़कें पानी से भर गईं। कई जगहों पर पानी की ऊंचाई तीन से चार फीट तक पहुंच गई, जिससे गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गईं। हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। प्रभावित इलाके मैरिन काउंटी में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक पानी कम न हो जाए, घरों में ही रहें। कुछ लोग सामान्य तौर पर सड़क रहने वाले इलाकों में कयाक चलाते नजर आए, जबकि कई लोग घुटनों तक पानी में चलकर बाहर निकले। सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र के लिए शनिवार दोपहर तक बाढ़ की चेतावनी और रविवार दोपहर तक बाढ़ की सलाह जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि किंग टाइड्स तब आती हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिससे समुद्र का जलस्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है।

14 साल बाद आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन की चीन यात्रा

डबलिन, एजेंसी। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन रविवार से चीन की पांच दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पिछले 14 वर्षों में किसी आयरिश नेता को यह पहली चीन यात्रा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि मार्टिन बीजिंग के अलावा शंघाई भी जाएंगे। वे चीनी प्रमुख ली कियांग के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोपीय संघ और चीन के बीच डेयरी उत्पादों और इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है।

यमन से अपने सैनिक वापस बुलाएगा यूएई

अबु धाबी, एजेंसी। पिछले कुछ दिनों की चेतावनी के बीच यूएई ने यमन से अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया है। यूएई ने कहा, वह यमन में चल रहे अपने आतंक-रोधी अभियान को खत्म कर रहा है। यह फैसला ऐसे समय किया गया है जब सऊदी अरब ने यूएई पर यमन के अलगगवादी गुट एसटीसी को समर्थन देने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले यमन की विपक्ष स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने यूएई से कहा था कि वह 24 घंटे में अपनी सेना यमन से हटा ले। यमन की इस मांग को सऊदी अरब का भी समर्थन मिला। इसके कुछ ही समय बाद ही यूएई ने अपनी सेना वापस बुलाने की घोषणा कर दी। सऊदी अरब नेतृत्व वाले गठबंधन ने कल यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हमला किया था। सऊदी का कहना था कि मुकल्ला पोर्ट पर जो जहाज पहुंचा था, उसमें यूएई से हथियार भेजे गए थे।

मादुरो की तरह पुतिन का भी हो हाल? :जेलेंस्की

वाशिंगटन, एजेंसी। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी और से नाटकीय ढंग से पकड़े जाने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वाशिंगटन अब तानाशाहों से निपटने के लिए आगे क्या करना है यह जानता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जेलेंस्की से मादुरो की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ? अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है, तो अमेरिका जानता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। उनका यह बयान साफ तौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर संकेत माना जा रहा है। इस बीच रूस ने अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को रिहा करने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मादुरो वेनेजुएला के वैध रूप से चुने गए राष्ट्रपति हैं और अमेरिका को उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए। रूस ने यह भी जोर दिया कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच विवादों का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए।

स्विस बार अग्निकांडः 48 घंटे बाद भी 6 घायलों की पहचान नहीं

बर्न, एजेंसी। स्विटजरलैंड के आल्प्स स्थित स्की रिसॉर्ट में नए साल के जश्न के दौरान को नॉस्टेलेशन बार में लगी भीषण आग में 40 लोगों की मौत के 48 घंटे बाद भी 6 घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। लापता लोगों के परिजनों की उम्मीद अब इन्हीं पर टिकी हुई है। जानकारी के मुताबिक, 119 घायलों में से 113 की पहचान हो चुकी है। भीषण रूप से जलने के कारण शवों और घायलों की पहचान मुश्किल हो गई है।

दक्षिण अमेरिकी देशों पर कब्जे की तैयारी में ट्रंप? वेनेजुएला के बाद क्यूबा को भी धमकी

वाशिंगटन, एजेंसी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अब अमेरिका की ट्रंप सरकार के हौसले बुलंद हैं और अब वे दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों को भी धमकाने पर उतर आए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा के नेता को चेतावनी देते हुए कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद अगर मैं क्यूबा की सरकार में होता तो यकीनन मुझे चिंता होती।

मार्को रूबियो ने क्यूबा को दी चेतावनी : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'क्यूबा पूरी तरह से तबाह है। इसे पूरी तरह से अयोग्य सरकार और इसे एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं बची है। यह पूरी तरह से तबाह देश है। मादुरो की सुरक्षा में लगे सभी

गाइ भी क्यूबा के थे। क्यूबा ने कुछ मामलों में वेनेजुएला पर कब्जा किया हुआ है। क्यूबा ने वेनेजुएला को अपनी कालोनी बनाने की कोशिश की। अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखें तो अगर मैं हवाना में रह रहा होता और मैं सरकार में होता तो मैं घटनाक्रम से थोड़ा चिंतित तो जरूर होता।'

अमेरिका और क्यूबा के बीच रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण हैं। दोनों देशों के संबंधों में तनाव 1960 के दशक से है, जब फिदेल कास्त्रो की सरकार के साथ अमेरिका के संबंध बिगड़े और अमेरिका ने क्यूबा पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। बराक ओबामा के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध सुधारने की कोशिश हुई, लेकिन ट्रंप और बाइडन सरकार में फिर से संबंध तनावपूर्ण हो गए।

ट्रंप ने भी दिए संकेत : गौरतलब है कि

कौन हैं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति? मादुरो की करीबी डेल्सी रोड्रिज़ को मिली जिम्मेदारी

काराकास , एजेंसी। अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में मंचे भारी राजनीतिक घमासान के बीच देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिज़ को देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार सभालने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि यह निर्णय देश की संप्रभुता और प्रशासनिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है।

कौन हैं डेल्सी रोड्रिज़ : 56 साल की डेल्सी रोड्रिज़ वेनेजुएला की राजनीति का एक कड़ावर और अनुभवी चेहरा हैं। वे एक क्रांतिकारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता, जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिज़ एक वामपंथी गुरिल्ला नेता थे। कानून की पढ़ाई करने वाली डेल्सी पिछले एक दशक में मादुरो सरकार की सबसे भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभरी हैं। वह मादुरो सरकार की सशक्त समर्थक रही हैं। मादुरो ने अपनी सरकार का समर्थन करने के लिए डेल्सी को 'शेरीन' तक कहा था।

डेल्सी रोड्रिज़ का राजनीतिक सफर : उन्होंने 2013 से 2017 के बीच सूचना और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली। जून 2018 में मादुरो ने उन्हें देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया। मादुरो अक्सर उन्हें 'हजारों लड़ाइयों में परखी हुई एक बहादुर क्रांतिकारी' कहते रहे हैं। अगस्त 2024 में उन्हें तेल मंत्री का



अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था ताकि वे अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सकें।

मादुरो को बताया देश का इकलौता राष्ट्रपति : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक ऑडियो संदेश में डेल्सी रोड्रिज़ ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने अमेरिकी हिरासत में मौजूद निकोलस मादुरो को ही देश का एकमात्र वैध राष्ट्रपति बताया और अमेरिका से उनके जिंदा होने के सबूत मांगे। उन्होंने कहा, 'इस देश का केवल एक ही राष्ट्रपति है और उनका नाम निकोलस मादुरो मोरोस है।

ट्रंप के दावे और विरोधाभास : डेल्सी का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के ठीक उलट है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि रोड्रिज़ ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और वे वाशिंगटन के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया था कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला का

सरकार की अहम नीतियों पर काम करती रही है। डेल्सी रोड्रिज़ ने अपने राजनीतिक करियर में सरकार के कई अहम पदों पर काम किया है। वर्ष 2013 से 2014 तक वह संचार और सूचना मंत्री रहीं, इसके बाद 2014 से 2017 तक उन्होंने विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। साल 2017 में उन्हें सरकार समर्थक संविधान सभा का प्रमुख बनाया गया, जिसने मादुरो सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जून 2018 में डेल्सी रोड्रिज़ को वेनेजुएला का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वहीं अगस्त 2024 में उन्हें तेल मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने अमेरिका के बढ़ते प्रतिबंधों के बीच देश के सबसे अहम उद्योग को संभालने और उसे स्थिर रखने की कोशिश की।

पेशे से वकील डेल्सी रोड्रिज़ ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला से पढ़ाई की है। अपने स्टाल और डिजाइनर फैशन के शौक के लिए भी वह जानी जाती हैं। पिछले एक दशक में उन्होंने तेजी से राजनीतिक ऊंचाइयां हासिल कीं और आज वेनेजुएला की सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हैं। मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी कर अमेरिका से निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस के सुरक्षित होने का सबूत देने की मांग भी की थी।

वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र की सख्त चेतावनी, गुटेरेस बोले- बन सकती है खतरनाक मिसाल

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी।

अमेरिका के तर्फ से वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई को लेकर वैश्विक राजनीति में हलचल तेज है। इसी बीच अब संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने अमेरिका के इस सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया कि महासचिव वेनेजुएला में हालिया घटनाओं से बेहद चिंतित और परेशान हैं। बयान में कहा गया कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से न सिर्फ वेनेजुएला, बल्कि पूरे क्षेत्र में हालात बिगड़ सकते हैं।

इस दौरान गुटेरेस ने साफ कहा



कि वेनेजुएला की स्थिति चाहे जैसी भी हो, किसी देश में इस तरह की सैन्य दखल अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने चिंता जताई कि इस पूरे घटनाक्रम में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान नहीं किया गया।

यूएन महासचिव की अपील : महासचिव ने सभी पक्षों से अपील की कि वेनेजुएला में

बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए, जिसमें सभी को शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस सभी प्रक्रियाओं में मानवाधिकारों और कानून के शासन का पूरी तरह पालन होना चाहिए।

मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने भी जताई चिंता : वहीं, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने भी अमेरिका की कार्रवाई पर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी देशों को संयम बरतना चाहिए और ह चार्टर व अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का सम्मान करना चाहिए।

वोल्कर तुर्क ने कहा कि वेनेजुएला के आम लोगों की सुरक्षा सबसे अहम है और आगे होने वाली किसी भी कार्रवाई में

लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस बयान के बाद साई है कि वेनेजुएला में अमेरिकी दखल को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं और संयुक्त राष्ट्र इस पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है।

वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई : गौरतलब है कई महीनों से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी तनाव ने एक बड़ा रूप तब ले लिया, जब वेनेजुएला की राजधानी काराकास शुक्रवार देर रात (स्थानीय समयानुसार) अमेरिकी हमलों से दहल उठी। अमेरिकी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। इसके बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वेनेजुएला पर अब अमेरिका का नियंत्रण होगा, जब तक वहां शांति स्थापित नहीं हो जाती।

‘दंगाइयों को उनकी जगह दिखाओ’, विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की धमकी

तेहरान, एजेंसी। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का बयान सामने आया है। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को धमकी दी है और सुरक्षाबलों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। खामेनेई ने कहा कि जो दंगाई हैं, उन्हें उनकी जगह दिखाई जाए। खामेनेई का बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान में आर्थिक संकट को लेकर बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। इन विरोध प्रदर्शनों में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। खामेनेई के इस बयान को ईरान के सुरक्षा बलों के लिए खुली छूट माना जा रहा है और अब वे प्रदर्शनकारियों पर और सख्ती बढ़ा सकते हैं।

खामेनेई ने विदेशी ताकतों पर लगाए साजिश रचने के आरोप : ईरान के राष्ट्रीय टीवी पर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का बयान जारी किया गया। इस बयान में खामेनेई ने कहा, 'हम प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों को भी प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। दंगाइयों को उनकी जगह पर पहुंचना चाहिए।' खामेनेई ने विरोध प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों के हाथ होने का दावा किया। उन्होंने कहा, 'दुश्मनों द्वारा खरीदे गए कुछ लोग इस विरोध प्रदर्शन के पीछे हैं, जो दुकानदारों और प्रदर्शनकारी लोगों के पीछे से ईरान, ईरानी गणराज्य और इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।'

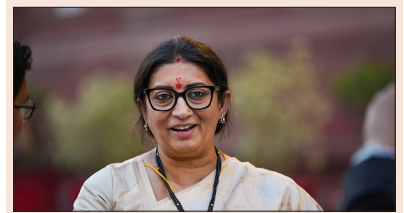
अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन : ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के अभी थमने के आसार नहीं लग रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर दिया



है। उन्होंने एक बयान में कहा कि अगर ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करती है तो अमेरिका उनके बचाव में आएगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरान की सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर हमले की धमकी दी है। ईरान में साल 2022 में भी एक 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। महसा अमीनी को बुर्का न पहनने के लिए प्रताड़ित किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। 2022 के बाद ईरान में अब इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

ईरान के कट्टरपंथी नेता प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेकिशनन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के पक्ष में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान में साल 2019 में ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में 300 लोगों की मौत हुई थी। वहीं महसा अमीनी की मौत के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 22 हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था।

उनकी असली जीत हार में है, क्योंकि हार ने उन्हें सिखाया और जीवन की दिशा दी : स्मृति ईरानी



जयपुर (एजेंसी)। सीतापुरा स्थित जयपुर एजीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राजस्थान डिजिटल टाई ग्लोबल समिट-2026 में सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा पर खुलकर अपनी बात रखी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ईरानी ने बताया कि उनकी असली जीत हार में है, क्योंकि हार ने उन्हें सिखाया और जीवन की दिशा दी। सत्र में उन्होंने महिलाओं की तकनीक, नीति, स्टार्टअप और सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी पर जोर दिया। मल्टीटास्किंग और दृढ़ता को अपने करियर की कुंजी बताते हुए उन्होंने चुनाव हारने के अनुभवों से मिली सीखों का उल्लेख किया। उन्होंने महिला उद्यमियों के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों, अवसरों और चेंसरशिप की आवश्यकता पर भी चर्चा की। ईरानी ने 9 करोड़ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नए भारत की उजली तस्वीर बताते हुए अपनी पहलें साझा की—1 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना, 300 स्टार्टअप को बढ़ावा देना और 100 मिलियन डॉलर से अधिक का फंड जुटाना। उन्होंने कहा कि ये कदम महिलाओं के उद्यमिता इकोसिस्टम को मजबूत करने, अवसर और पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करने की लंबी अवधि की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

टाटा हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी ,हॉस्पिटल खाली कराया गया

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई के परेल इलाके में स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की एक अनजान धमकी मिलने के बाद सोमवार को हड़कंप मच गया। इस धमकी के बाद पुलिस विभाग और हॉस्पिटल प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गए हैं और एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल केफैस खाली करा लिया गया है। धमकी भरा कॉल या मैसेज मिलते ही मुंबई पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। फिलहाल, बम डिटेक्शन एंड डिपोजल स्कॉड (बीडीडीएस) मौके पर पहुंच गया और डॉग स्कॉड की मदद से हॉस्पिटल के हर फ्लोर और कोने की अच्छी तरह से जांच की गई। पुलिस उपायुक्त समेत वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। चूंकि टाटा हॉस्पिटल देश में कैंसर के इलाज का सबसे बड़ा सेंटर है, इसलिए यहां हर दिन हजारों मरीज और उनके रिश्तेदार आते हैं। बम की खबर फैलते ही इलाके में डर का माहौल बन गया। सुरक्षा कार्पोने से अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया और ओपीडी एवं दूसरी भीड़भाड़ वाली जगहों को खाली कर दिया गया। इस दौरान यहां अफरातफरी का माहौल तो रहा ही मरीजों तथा उनके रिश्तेदारों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। फ़िलहाल पुलिस जांच कर रही है कि यह सिर्फ अपवाद है या हमले की कोशिश। धमकी किस नंबर या माध्यम से आई, इसकी तकनीक जांच की जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने अपील की है, लोगों को घबराना नहीं चाहिए, पुलिस पूरी जांच कर रही है।

झारखंड में दो घटनाओं में जंगली हाथियों ने महिला व युवक को कुचलकर मार डाला

रांची (एजेंसी)। झारखंड में अलग-अलग घटनाओं में जंगली हाथियों के हमले से दो लोगों की मौत हो गई। वन अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान पश्चिम सिंहभूम जिले के कितापी गांव की चंपा कुई (47) और लातेहार जिले के मतनाग गांव के वीरेंद्र कोरवा के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक चंपा कुई रविवार तड़के करीब साढ़े बार बजे अपने घर से बाहर निकली थीं, तभी एक हाथी जो झुंड से भटक गया था, गांव में आ गया और उसने चंपा को कुचल दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और परिवार को अंतरिम राहत के रूप में 20,000 रुपये की सहायता राशि दी। विभाग ने परिजनों को औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद सरकारी प्रावधानों के मुताबिक मुआवजा प्रदान करने का आश्वासन दिया। लातेहार जिले में चिचदोहार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतनाग गांव में शाम करीब चार बजे एक हाथी ने कोरवा को कुचलकर मार डाला। कोरवा चौक बाजार से घर जा रहा था तभी हाथियों के एक झुंड ने उसे घेर लिया और मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही रेंजर और वनपाल समेत वन विभाग की एक टीम घटना की जांच के लिए मौके पर पहुंची।

8 साल 4 माह की सजा में 387 दिन बाहर, राम रहीम की मनमर्जियां कब रुकेगी ?

गुरग्राम (एजेंसी)। अपनी दिश्याओं से रेप में 20 साल की जेल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को फिर 40 दिन की परोल मिली। राम रहीम अभी हरियाणा में रहेतक के सुनारिया जेल में बंद हैं। इसके पहले हिराएल पाल अगस्त में 40 दिन की परोल मिली थी। इस हिराएल पाल से पहले खम रहीम 2017 में दोषी ठहरने के बाद से 14 बार जेल से बाहर आ चुका है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जैसी संगठनों ने राहत देने की आलोचना की है। जेल से बाहर आने के बाद वह कई बार बागपत स्थित डेरा के आश्रम में रहा।

1. 24 अक्टूबर 2021 को 1 दिन की परोल, बीमार मां के लिए।
2. 21 मई, 2021 : 1 दिन की, बीमार मां के लिए फिर।
3. 7 फरवरी, 2022 : 21 दिन की, पंजाब में चुनाव थे।
4. 17 जून, 2022 : 30 दिन, हरियाणा निकाच चुनाव थे।
5. 15 अक्टू, 2022 : 40 दिन की, आदमपुर उपचुनाव थे।
6. 21 जनवरी 2023 : 40 दिन, शाह सतनाम जयंती थी।
7. 20 जुलाई, 2023 : 30 दिन, 15 अगस्त को बर्थडे था।
8. 21 नवंबर, 2023 : 21 दिन, राजस्थान में चुनाव थे।
9. 19 जनवरी, 2024 : 50 दिन, लोकसभा चुनाव होने थे।
10. 13 अगस्त, 2024 : 21 दिन, 15 अगस्त को बर्थडे था।
11. 1 अक्टूबर, 2024 : 21 दिन, हरियाणा में चुनाव थे।
12. 28 जनवरी, 2025 : 30 दिन, दिल्ली में चुनाव थे।
13. 9 अप्रैल, 2025 : 41 दिन, डेरे का स्थापना दिवस था।
14. 5 अगस्त, 2025 : 40 दिन, 15 को बर्थडे था।

2027 में सत्ता में लौटाने के लिए आतुर अखिलेश ने तैयार किया चुनावी मिशन 84

अखिलेश की रणनीति से बसपा और बीजेपी को लग सकता है झटका

लखनऊ (एजेंसी)। वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) ने अभी से कमर कस ली है। 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ऐसी रणनीति तैयार की है, जिससे प्रदेश की जातीय राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। अखिलेश की इस रणनीति के केंद्र में राज्य की वे 84 विधानसभा सीटें हैं, जो अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हैं, साथ ही कई सामान्य सीटें भी हैं, जहां दलित वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अखिलेश की इस सक्रियता से न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की टेंशन बढ़ी है, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा कर दिया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक लंबे समय से बसपा की ताकत रहा है।

लेकिन बीते कुछ चुनावों में बसपा के कमजोर प्रदर्शन और संगठनात्मक ढील के कारण यह वोट बैंक बिखरता दिखा है। इस मौके के फायदा उठाकर अखिलेश ने दलित समुदाय को सपा से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी का मानना है कि अगर बसपा के कोर वोट बैंक में संघ लगाने में सफलता मिलती है, तब 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर करना आसान होगा। दरअसल अखिलेश यादव की यह चुनावी रणनीति उनके 'पीडीए' फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को एकजुट करने का लक्ष्य रखा गया है। सपा नेतृत्व का मानना है कि यही सामाजिक गठजोड़ यूपी की राजनीति का भविष्य तय करेगा। इसी सोच के तहत पार्टी ने फैसला किया है कि वह केवल आरक्षित सीटों तक सीमित न रहकर सामान्य

सीटों पर भी बड़ी संख्या में दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। इससे दलित समाज में यह संदेश जाएगा कि सपा उन्हें सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि नेतृत्व का मौका देना चाहती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, सपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों से अहम सबक लिया है। उस चुनाव में दलित वोटों का एक हिस्सा सपा के पक्ष में आया था, जिसने पार्टी के प्रदर्शन को मजबूती दी। अब सपा चाहती है कि विधानसभा चुनाव में समर्थन को और व्यापक रूप दिया जाए। इसी उद्देश्य से 2025 से ही 'पीडीए चर्चा' कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चलाए जा रहे हैं। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सपा का यह दांव पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है। सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने से



सर्वण और अन्य वर्गों के कुछ वोट खिसकने का खतरा भी है। बावजूद इसके, सपा नेतृत्व का भरोसा है कि व्यापक सामाजिक गठबंधन इस नुकसान की भरपाई कर सकता है। अखिलेश यादव खुद कई मौकों पर कह चुके हैं कि 'पीडीए ही यूपी का भविष्य है'।

मुख्यमंत्री सिद्धारमेया ने कहा, जनता के आशीर्वाद से देवराज उर्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा

बेंगलुरु । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमेया ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उर्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा। उन्होंने बताया कि देवराज उर्स भी मैसूर जिले के निवासी थे और उनका रिकॉर्ड भविष्य में कोई भी तोड़ सकता है। सिद्धारमेया ने 1983 के विधानसभा चुनावों का जिक्र कर कहा कि उस समय लोग वोट और धन से समर्थन देते थे, जबकि अब परिस्थितियां अलग हैं। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा, वैसे ही भविष्य में कोई मुख्यमंत्री उनसे अधिक समय तक पद संभाल सकता है या अधिक बजट पेश कर सकता है। प्रस्तावित उपकरण सम्मेलन पर उन्होंने कहा कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और कार्यक्रम का आयोजन कृष्णा भेरेगोड़ा करेंगे। कैबिनेट फेरबदल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में राहुल गांधी से चर्चा करूंगा और जनवरी में फोन आने पर वे जाएंगे। बल्लारी मामले पर सीएम ने कहा कि भाजपा मौजूदा न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग कर रही है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले रिपोर्ट आने दी जाए, फिर जांच तय होगी। वीवीजी राम की गारंटी आलोचना पर प्रतिक्रिया देकर सिद्धारमेया ने कहा कि 3,000 करोड़ रुपये का 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार पर बोझ डालेगा। सिद्धारमेया का बयान साफ करता है कि राजनीतिक रिकॉर्ड समय के साथ टूटते हैं और भविष्य में किसी भी नेता के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करना संभव है।



तेलंगाना की जनता को धोखा देने के लिए राहुल गांधी और सीएम रेडडी को फांसी देना चाहिए: रामाराव



हेदराबाद (एजेंसी)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवेंत रेड्डी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तेलंगाना की जनता को धोखा देने के लिए कई बार फांसी देना चाहिए। बीआरएस नेता रामाराव का यह बयान मुख्यमंत्री रेड्डी की पिछली टिप्पणियों के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की कड़ी आलोचना कर नदी जल बंटवारे में तेलंगाना के हितों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने और सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से अवैध रूप से धन कमाने के लिए उन्हें मृत्युदंड देने की मांग की थी।

मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देकर केटीआर ने कहा कि अगर टूटे वादों को भी ध्यान में रखा जाए, तब यह हिसाब लगाना मुश्किल है कि कांग्रेस नेताओं को कितनी बार फांसी दी जाए। उन्होंने कहा कि राहुल

गांधी द्वारा अशोक नगर अड्डा में दो लाख नौकरियों का वादा पूरा न करने, वारांगल में कृषि ऋण माफी योजना लागू न करने और कामरेड्डी में बीसी समुदाय के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण के वादे से मुकदमे के लिए कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ जनता को अपना फैसला सुनाना चाहिए। उन्होंने आलोचना कर कहा कि 420 वादों को तोड़ने के लिए कांग्रेस जनता द्वारा 420 बार दंडित किए जाने की पात्र है।

पार्टी के बयान के अनुसार, केटीआर ने कहा कि सीएम रेड्डी को केवल गाली देना आता है, जबकि बीआरएस जरूरत पड़ने पर तीन-चार भाषाओं में जवाब देने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आईआईटी और आईआईआईटी के बीच या बाचावत ट्रिब्यूनल और वृजेश कुमार ट्रिब्यूनल के बीच अंतर नहीं जानता, उसके लिए तेलंगाना के भविष्य के बारे में बात करना हास्यास्पद है।

केरल प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने वेल्लापल्ली नटेसन से की मुलाकात... सियासी गलियारों में चर्चा तेज

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल में भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाया है। पार्टी के केरल प्रभारी और वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने एसएनडीपी योगम के जनरल सेक्रेटरी वेल्छपल्ली नटेसन से उनके आवास पर मुलाकात की। यह बैठक तब हुई जब नटेसन द्वारा पत्रकार को आतंकवादी कहने वाले बयान ने विवाद पैदा किया था। मुलाकात के बाद बीजेपी नेता जावड़ेकर ने मंत्रीपूर्ण दौरा बताकर कहा कि उन्हें नटेसन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। उन्होंने नटेसन के प्रारंभिक दिनों में एसएनडीपी योगम की स्थापना और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत हमेशा सुखद और सकारात्मक रही है, इसलिए इसमें कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। भाजपा के इस कदम को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि नटेसन के हाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के करीब आने की खबरें आई थीं। जावड़ेकर ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की जीत का उल्लेख करते हुए गुजरात के अहमदाबाद जैसी



उपलब्धि बताया। नटेसन ने हाल ही में मुस्लिम बहुल मलपपुरम जिले में एसएनडीपी के शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति नहीं मिलने पर टिप्पणी की थी, साथ ही एक पत्रकार को चरमपंथी बताते वाले बयान ने विवाद बढ़ाया। संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जबकि माकपा और भाजपा ने कोई निंदा नहीं की। नटेसन के बेटे टी. वेल्छपल्ली

भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजन) से जुड़ी है। इस बैठक का राजनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव के पूर्व केरल में विभिन्न दल अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं और भाजपा के लिए यह कदम समुदायों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने का संकेत माना जा रहा है।

अग्निवीरों को सेना में परमानेंट होना है तो शादी करने से मना करना होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना की अग्निवीर योजना एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि साल 2022 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का पहला बैच अब अपनी चार साल की सेवा पूरी करने के करीब है। जून और जुलाई के महीनों में लगभग 20 हजार से अधिक अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। इस मोड़ पर हजारों युवाओं के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सेना ने स्थायी होने की प्रक्रिया और उससे जुड़े कड़े नियमों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अग्निवीरों को सेना में परमानेंट होना है तो शादी करने से मना करना होगा।

सेना ने स्पष्ट किया है कि अग्निवीर अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान विवाह नहीं कर सकते। नियमों की गंभीरता यही खत नहीं होती, सेवा से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद भी उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं होगी। स्थायी सैनिक बनने की चयन प्रक्रिया, जो लगभग 4 से 6 महीने तक चल सकती है, के दौरान भी उम्मीदवारों का अविवाहित रहना अनिवार्य है। अंतिम परिणाम घोषित होने और आधिकारिक रूप से स्थायी कमीशन मिलने तक यह नियम लागू रहेगा। सेना के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों में से केवल 25 प्रतिशत को ही

स्थायी सैनिक के रूप में दोबारा नियुक्त किया जाएगा। यह चयन पूरी तरह से उनके पिछले प्रदर्शन, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के अंकों पर आधारित होगा। हालांकि, योग्यता के साथ-साथ अनुशासन को सबसे ऊपर रखा गया है, जिसमें वैवाहिक स्थिति को लेकर बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं।अनुशासन पर जोर देते हुए सेना ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अग्निवीर इस निर्धारित अवधि के दौरान शादी करता है, तो उसे स्थायी नौकरी के लिए अयोग्य मान लिया जाएगा। भले ही उस उम्मीदवार का पेशेवर रिकॉर्ड और शारीरिक प्रदर्शन कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, नियम उल्लंघन की स्थिति में

उसे चयन प्रक्रिया से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। आमतौर पर अग्निवीरों की भर्ती 21 वर्ष तक की आयु में होती है और वे लगभग 25 वर्ष की आयु में सेवानुक्त होते हैं। सेना का मानना ​​है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर नियमों का पालन करना न केवल सैन्य अनुशासन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक सैनिक की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। केवल वही अग्निवीर स्थायी कमीशन के पात्र होंगे जिन्होंने अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिनका रिकॉर्ड बेदाग हो और जिन्होंने सेवा की पूरी अवधि में ब्रह्मचर्य और अविवाहित रहने के मानदंडों का पालन किया हो।

